एपेलेट कोर्टस में । देहात वालों को इन्साफ मिले इसके लिए जरूरी है कि कानून से वाकिफ आदमी, कोई लायर वहां जायें । उस सूरत में तमाम लिटिगेंट पब्लिक को और तमाम देहात वालों को रूडीमेंट्स आफ ला से वाकफियत होगी और इससे नेशनल काज़ भी सर्व होगा ।

दूसरी बात यह है कि जो लायर है वह सालिसिटर जनरल हो सकता है, एडवोकेट जनरल हो सकता है और गवर्नमैंट से दो दो और तीन तीन हजार रुपया महीना भी ले सकता है । वह एम पी और एम एल ए भी बन सकता है । ऐसी सूरत में राजस्थान ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसमें कौन सी सैंस है कि वह आप्रेटिव हो ? क्या मन्त्री महोदय रिकोमेंड करेंगे वहां की बार काउन्सिल को कि यह रेजोल्यूशन इन दी लाइट आफ दी रेजोल्यूशन आफ दी आल इन्डिया बार काउंसिल इनआप्रेटिव है ?

श्री मु० यूनस सलीम : खाली रिम्युनरेशन काफी नहीं हैं । अगर कोई एडवोकेट जनरल या सालिसिटर जनरल या गवर्नमैंट एडवोकेट रिम्युनरेशन लेता हैं तो वह अपने पेशे का ही काम करता हैं ।

> Therefore, the criterion is a person who is receiving honorarium as remuneration and also enjoying wide executive powers.

श्री मोठा लाल मीना : ग्राम पंचायतों के प्रधान और जिला परिषद् के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हैं । एम पीज़ और एम एल एज़ को कोई भी प्रशासकीय अधिकार प्राप्त नहीं है । जिला परिषद के प्रमुख और जिला पंचायत समिति के प्रधान यदि एडवोकेट का भी धन्धा करेंगे और प्रशासकीय भी धन्धा करेंगे तो यह न्याय के लिए एक खतरा होगा । इस वास्ते जो नियम बनाया है वह बिल्कुल सही बनाया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानून पास करके इसकी मान्यता प्रदान की जायेगी ?

श्री मु० यूनस सलीम : एक्ट के तहत बार काउंसिल को रूल बनाने का अख्त्यार हैं और बार काउंसिल जिस तरह से मुनासिब समझेगी एक्ट की स्पिरिट के पेशे नजर रूल बनायेगी ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Plan for Rapid Development of Harijans, Tribals and Backward Classes

*842. SHRI A. SREEDHARAN : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state.

(a) whether in view of the prolonged delay in securing the minimum basic amenities to the Harijans, the Tribals and the backward classes and ensuring them the minimum standards of living, Government propose to draw up any plan for rapid development of these classes under the Fourth Five Year Plan before giving any additional facilities to any other class of people in the country;

(b) if so, the details of such development plan; and

(c) by what time the minimum necessities of life are likely to be ensured to the said depressed classes in pursuance of the said plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA) : (a) to (c) . The problem of bringing about widespread changes in the socio-economic conditions of the weaker sections of society, in a country which is itself underdeveloped, in one which does not lend itself to quick or radical remedies. The development measures already taken in hand since 1950 have yielded appreciable results, and these efforts will have to continue for some time.

Subsidy for export of Sugar

*848. SHRI R. K. AMIN : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government continue to give subsidy for export of sugar; and

(b) the reasons for following such a policy of spending a larger amount on sub-

sidy than what is earned in foreign exchange ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) No, Sir. Government is not giving any subsidy on exports in the current year 1968.

(b) The question does not arise.

Hindustan Teleprinters, Limited

*849 SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether at any time a general assessment of the working of the Hindustan Teleprinters Ltd. had been done; if so what was the result, and

(b) whether Government have any idea of securing the services of any expert in order to find out the drawbacks and to bring about improvment in its working ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) The performance of the Hindustan Teleprinters Ltd. is being regularly watched. The Company is making steady progress and no general assessment of the working of the Company has been considered necessary. The Company has declared a dividend of 10% for the year 1967-68.

(b) Does not arise in view of the reply to part (a) of the question.

कालकाजी नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को प्लाटों का अलाट किया जाना

*850 **श्री रणजीत सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी कालोनी नई दिल्ली में लगभग 3000 प्लाट आवंटित किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये प्लाट उन्हें अभी तक नहीं दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) बस्ती में बनाये गये 2117 प्लाटों में से 1365 प्लाट लाटरी निकाल कर पहले ही अलाट किये जा चुके हैं।

(ख) और (ग). आवेदक को भूमि के प्लाट की पेशकश करने के उपरान्त उसे प्लाट के लिए दिये जाने वाले प्रिमियम की अनुमानित राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाना पड़ता था। उसके उपरान्त लाटरी निकाल कर प्लाट अलाट कर दिये गये थे। उसके बाद अलाटियों को, प्रिमियम की चुकाई जाने वाली शेष 7 किश्तों में से, प्रथम किश्त जमा करवाने के लिए कहा गया हैं। कुछ अलाटियों ने समय-सीमा बढ़ाने के लिए कहा हैं और अन्य 1103 अलाटियों ने प्रथम किश्त जमा कर दी हैं। जिन्होंने किश्त जमा करा दी हैं उन्हें आवश्यक करार भरने के लिए कहा जा रहा हैं। अब तक केवल 9 व्यक्तियों ने ही करार भरे हैं और उनमें से 7 को बस्ती में इस प्रयोजन के लिए लगाये गये अधिकारी से अपने प्लाटों का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया हैं।

उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव

*851 **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में छः वर्षों से भी अधिक समय से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव तुरन्त